Budget Analysis Rajasthan Centre
बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

19 सितम्बर 2011

प्रेस विज्ञप्ति

जयपुर: बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, जयपुर, के द्वारा विकास अध्ययन संस्थान (IDS), झालाना डूंगरी, जयपुर में "राज्य चतुर्थ वित्त आयोग के संदर्भ में शहरी निकायों के प्रतिनिधियों एवं स्वयंसेवी संगठनों के साथ एकदिवसीय कार्यशाला" का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्वेश्य चतुर्थ राज्य वित्त आयोग को शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों के सुझाव एवं चिंताओं से परिचित करवाना था। कार्यशाला की अध्यक्षता चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री बी. डी. कल्ला ने की। कार्यशाला में वित्त आयोग की भूमिका, कार्यक्षेत्र एवं महत्त्व पर विस्तृत चर्चा की गई। इस कार्यशाला में जयपुर, कोटा तथा जोधपुर के महापौर सहित राज्य के तीस से अधिक शहरी निकायों के प्रतिनिधियों एवं स्वयंसेवी संगठनों ने भाग लिया।

कार्यशाला में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री बी. डी. कल्ला ने शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की। अपने अध्यक्षीय भाषण में, श्री कल्ला ने राज्य में स्थित शहरी निकायों को उनकी निजी आय बढ़ाने हेतु प्रयास करने पर जोर दिया। इसके लिए निकायों के अधिकार अंर्तगत आने वाली जमीनों पर वृक्षारोपण कर उनसे आय प्राप्त करना, दूकानें एवं मॉल बनवाकर उन्हें किराए पर देना आदि उपाय हो सकते हैं। श्री कल्ला ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र अपने अधिकार अंर्तगत आने वाले विषयों पर उपयुक्त कर एवं शुल्क वसूली कर निकायों की आमदनी के साथ साथ नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं में बढ़ोतरी का सकते हैं। उन्होने बताया कि निकायों के अधिकार क्षेत्र के अंर्तगत आने वाली भूमि उनके लिए आय प्राप्ति का सर्वोत्तम संसाधन है और इसके लिए निकाय प्रतिनिधियों को प्रयास करने चाहिए।

कार्यशाला में जयपुर महापौर श्रीमति ज्योति खंडेलवाल ने बताया कि चूंकि पहले से बकाया कर्जे के कारण शहरी निकायों की आय का एक बड़ा हिस्सा ब्याज अदायगी पर खर्च हो रहा है। इसलिए इन निकायों के पुराने कर्जे माफ किए जाने चाहिए अथवा उन्हे इसके लिए एक मुश्त राशि दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होने जोर दिया कि राज्य बजट में एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा इन निकायों को दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त श्रीमति खंडेलवाल ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाली योजनाओं में शहरी निकायों की भूमिका तय की जानी चाहिए इसके अतिरिक्त उन्होने बतौर हैरिटेज सिटी होने के नाते जयपुर शहर के सौंदर्यीकरण एवं विरासत के रखरखाव एवं संरक्षण हेतु अतिरिक्त अनुदान दिये जाने की मांग की।

अन्य शहरी निकायों के प्रतिनिधियों ने मांग की कि स्थानीय क्षेत्रों में खनन से प्राप्त रॉयल्टी की एक निश्चित प्रतिशत राशि इन निकायों को दी जानी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में स्थित सिवायचक की जमीनें इन निकायों को हस्तान्तरित की जानी चाहिए ताकि शहरी निकायों की आमदनी में वृद्वि हो सके। सभी प्रतिनिधियों ने शहरी निकायों

P-1, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur- 302005
Tel./Fax : (0141) 2385254
E-mail : info@barcjaipur.org   Website : www.barcjaipur.org

में स्टॉफ की कमी पर चिंता जताई साथ ही इन लोगों ने तीन चार वर्ष पूर्व तक शहरी निकायों को जनसंख्या के आधार पर मिल रहे अनुदान (15 रु. प्रति व्यक्ति) के बंद हो जाने को इन निकायों की खराब होती आर्थिक स्थिति का सबसे बड़ा कारण बताया। जनप्रतिनिधियों ने मांग की कि यह अनुदान इन पूर्व वर्षों में बढ़ी महंगाई के अनुरुप बढ़ाकर पुनः चालू किया जाना चाहिए। जनप्रतिनिधियों ने मोबाइल टावर, विवाह स्थलों पर कर लगाने की बात भी कही। प्रतिनिधियों ने मांग की कि शहरों की अन्य ऐजेंसियों जैसे विकास प्राधिकरण आदि तथा अन्य विभागों जैसे राजस्व विभाग से प्राप्त होने वाली आय में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

जोधपुर महापौर श्री रामेश्वर दाधिच ने बताया कि शहरी निकायों में पर्याप्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों का अभाव है जिनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। शहरी निकायों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए इसके लिए आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभाग पंचायतों की तरह शहरी निकायों को स्थानान्तरित किए जाने चाहिए। कोटा महापौर श्रीमति रत्ना जैन ने बताया कि राज्य में सरकारी सेवाओं के दौरान सफाई हेतु लगी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले डीजल के अपव्यय को रोकने के लिए एवं कार्यशैली में पारदर्शिता लाने हेतु कोटा नगर निगम की तर्ज पर इन गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होने बताया कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित फल, सब्जी एवं अनाज मंडियों के प्राप्त राजस्व अथवा शुल्क शहरी स्थानीय निकायों को दिया जाना चाहिए।

कार्यशाला में राज्य वित्त आयोग से शहरी निकाय जनप्रतिनिधियों के क्षमतावर्धन तथा निकायों के कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही तय करने से संबंधित सुझाव दिए जाने की अपेक्षा भी व्यक्त की गई। सत्र के अंत में बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र जयपुर के समन्वयक नेसार अहमद ने आगन्तुकों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यशाला का समापन किया।

नेसार अहमद
कॉर्डीनेटर, बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, जयपुर

P-1, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur- 302005
Tel./Fax : (0141) 2385254
E-mail : info@barcjaipur.org Website : www.barcjaipur.org